



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष १, अंक ११]

बुधवार, एप्रिल १, २०१५/चैत्र ११, शके १९३७

[पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक १७

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक १ अप्रैल, २०१५ ई. को. पुरःस्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११७ के अधीन प्रकाशन किया जाता है :—

L. A. BILL No. XVII OF 2015.

A BILL
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA MUNICIPAL
CORPORATIONS ACT.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक १७, सन् २०१५ ।

महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम में अधिकतर संशोधन संबंधी विधेयक ।

सन् १९४९ **क्योंकि**, इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम में अधिकतर संशोधन
का महा. करना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में, एतद्वारा निम्न अधिनियम बनाया
४९। जाता है :—

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम (संशोधन) अधिनियम, २०१५ कहलाए । संक्षिप्त नाम।

(१)

सन् १९४९ का
महा. ४९ की धारा
३१३ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा ३१३ में, परन्तुक के पश्चात्, निम्न परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

सन् १९४९
का महा. ४९।

“ परन्तु आगे यह कि, नगर निगम की अधिकारिता के क्षेत्र के भीतर, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में कारखानों, कार्यशाला या कार्यस्थल के संबंध में ऐसी किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी । ”।

उद्देश्यों तथा कारणों का वक्तव्य।

महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम (सन् १९४९ का ५९) की धारा ३१३, यह उपबंध करती है कि, कोई व्यक्ति, नगर आयुक्त के पूर्वअनुमति के अलावा, किसी कारखानों, कार्यशालाओं या कार्यस्थानों की किसी परिसर में, नये रूपसे स्थापित करना, एक जगह से दूसरी जगह हटाना, तीन वर्षों से कम न हो अवधि के लिये रोके जाने के पश्चात्, फिर खोलना या नवीकरण करना या क्षेत्र के आकार को बढ़ाना या विस्तार नहीं कर सकता है।

२. ऐसे में, कोई उद्योगपति जो, नगर निगम के अधिकारिता क्षेत्र के भीतर, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के औद्योगिक क्षेत्र में कारखाना, कार्यशाला या कार्यस्थल स्थापित करना चाहता है, उसे, उक्त औद्योगिक निगम के साथ ही साथ नगर निगम से अनुमति प्राप्त करनी होती है, जिसके परिणामस्वरूप, उद्योगों की स्थापना में अनुचित विलंब होता है।

३. केंद्र सरकार ने, “ मेक इन इंडिया ” अभियान अपनाया है, जिसका लक्ष्य स्वदेशी निवेश को बढ़ाना और औद्योगिक विकास को तेज करना है। उक्त “ मेक इन इंडिया ” अभियान के अनुसरण में, राज्य सरकार ने, “ कारोबार करने की सुगमता ” नीति के कार्यान्वयन द्वारा, “ मेक इन महाराष्ट्र ” अभियान कार्यान्वित करने का निश्चय किया है।

४. उक्त नीति के अनुसरण में, यह उपबंध करना प्रस्तावित है कि, यदि, कोई उद्योगपति, जो, नगर निगम की अधिकारिता क्षेत्र के भीतर, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के औद्योगिक क्षेत्र में, कारखाना, कार्यशाला या कार्यस्थल स्थापित करना चाहता है, जिसे उक्त औद्योगिक विकास निगम की अनुमति प्राप्त करनी हो तो, उसे उक्त धारा ३१३ के अधीन नगर आयुक्त की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

५. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

मुंबई,

दिनांकित ३० मार्च २०१५।

देवेंद्र फडणवीस,

मुख्यमंत्री ।

प्रत्यायुक्त विधान संबंधी ज्ञापन।

प्रस्तुत विधेयक में विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए, निम्न प्रस्ताव अन्तर्गृहीत है, अर्थात् :—

खंड २.— यह खंड, जिसका आशय, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा ३१३ में, उसमें नये परंतुक जोड़कर, उसके द्वारा, संशोधन करना है। उक्त परंतुक के अधीन, उक्त धारा ३१३ के प्रयोजन के लिए नगर निगम की अधिकारिता क्षेत्र के भीतर के क्षेत्र को अधिसूचित करने की शक्ति महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम को प्रदान की गई है, जिसके संबंध में नगर निगम आयुक्त की कोई कारखाना, कार्यशालाएँ, या कार्यस्थल स्थापन करने की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

विधायी शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए, उपरोलिखित प्रस्ताव सामान्य स्वरूप का है।

(यथार्थ अनुवाद),

स. का. जोंधळे,

भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन :

मुम्बई,

दिनांकित १ अप्रैल २०१५।

डॉ. अनंत कळसे,

प्रधान सचिव,

महाराष्ट्र विधानसभा।